

अध्याय–I

प्रस्तावना

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 उत्तर प्रदेश सरकार के 23 विभागों की लेखापरीक्षा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आती है। इस अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में परिशिष्ट-1 में वर्णित 16 विभागों और संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है और नीचे तालिका 1.1 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1.1: लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन विभागों और संस्थाओं की सूची

क्र. सं.	विभागों का नाम	संख्या		
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	अन्य संस्थाएँ (स्वायत्त निकाय/ प्राधिकरण, आदि)	योग
1	ऊर्जा विभाग	13	1	14
2	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	-	1	1
3	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	8	-	8
4	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	14	12 ¹	26
5	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग	7	-	7
6	परिवहन विभाग	1	-	1
7	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग	5	-	5
8	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	-	1	1
9	पर्यटन विभाग	1	-	1
10	नागरिक उड्डयन विभाग	-	-	-
11	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	-	-	-
12	संस्कृति विभाग	1	-	1
13	धर्मार्थ कार्य विभाग	-	-	-
14	लोक निर्माण विभाग	2	-	2
15	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1	2	3
16	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	2	2
योग		53	19	72

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

1.2 वर्ष 2021-22 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों के अन्तर्गत कुल 2,040 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 106 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित किया। इस प्रतिवेदन में 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों', 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा के परिणाम तथा सात विभागों² एवं पीएसयू/संस्थाओं से सम्बन्धित 14 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है।

¹ इसमें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) की चार विभागीय प्रबंधित इकाइयों अर्थात् राजकीय मुद्रणालय सम्मिलित है।

² ऊर्जा विभाग; अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग; सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; पर्यटन विभाग; लोक निर्माण विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग।

लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया

1.3 लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए चार चरणों में अवसर प्रदान करती है, जैसे

लेखापरीक्षा ज्ञापन: लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है, जिनका उत्तर उन्हें लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर): लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर जारी किया जाता है, जिस पर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देना होता है।

ड्राफ्ट प्रस्तर: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनको शामिल करने से पूर्व विचार करने हेतु विभागों के प्रमुखों, जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाइयाँ कार्य करती हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाते हैं।

समापन गोष्ठी: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर विभाग/शासन के विचारों को प्राप्त करने हेतु विभागों के प्रमुख और राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों के प्रमुख/राज्य सरकार को खंडन और स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने को प्रयत्नशील रहती हैं और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं अथवा स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं, तभी लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को निरीक्षण प्रतिवेदन या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है। हालाँकि, ज्यादातर प्रकरणों में लेखापरीक्षित संस्थाएँ समय पर एवं संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है।

• निरीक्षण प्रतिवेदनों की उत्तर की स्थिति

16 विभागों से सम्बन्धित 1,129 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को मार्च 2021 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2021 तक स्वीकार्य योग्य उत्तर की प्रत्याशा में 8,201 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 38,596 प्रस्तर निराकरण हेतु लंबित थे। इनमें से, 557 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 3,168 प्रस्तरों के प्रारम्भिक उत्तर डीडीओ द्वारा प्रस्तुत किये गए थे, जबकि 7,644 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 35,428 प्रस्तरों के सन्दर्भ में डीडीओ से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति तालिका 1.2 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.2: 31 मार्च 2021 तक लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों (31 मार्च 2021 तक जारी किये गए) की स्थिति

क्र. सं.	अवधि	लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	लम्बित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	2020-21	133 (1.62)	1,149 (2.98)
2	1 वर्ष से 3 वर्षों तक	1,199 (14.62)	8,064 (20.89)
3	3 वर्षों से 5 वर्षों तक	1,283 (15.65)	6,451 (16.71)
4	5 वर्षों से अधिक	5,586 (68.11)	22,932 (59.42)
योग		8,201 (100)	38,596 (100)

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की एक बैठक (लेखापरीक्षा समिति बैठक) आयोजित की गई।

• लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2020-21 में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तारों के उत्तरों की स्थिति

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2020-21 के लिए, 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों', 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं 14 लेखापरीक्षा प्रस्तारों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उनके विचार जानने के लिए अग्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा और लेखाओं पर विनियम, 2020 (विनियम, 2020) के विनियम 138 में प्रावधान है कि सम्बन्धित विभाग के सरकार के सचिव निर्दिष्ट समय के अन्दर ड्राफ्ट प्रस्तर के उत्तर प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने विनियम, 2020 के विनियम 138 को संदर्भित करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिया (सितम्बर 2020) कि वे विनियम, 2020 में परिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रस्तुत करें। मात्र एक लेखापरीक्षा प्रस्तर के सम्बन्ध में सरकार का उत्तर/प्रतिक्रिया प्राप्त हुआ है। 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों', 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' एवं 13 लेखापरीक्षा प्रस्तारों के सम्बन्ध में सरकार का उत्तर अनुस्मारकों के बावजूद अभी भी प्रतीक्षित (सितम्बर 2022) हैं। हालाँकि, 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' एवं 11 प्रस्तारों के सम्बन्ध में प्रबंधन के उत्तर प्राप्त हो गए हैं जिन्हें सम्मिलित कर लिया गया है।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही

1.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तारों पर लम्बित उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यपालिका से उपयुक्त एवं समय से उत्तर प्राप्त हों। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तारों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधान मण्डल में प्रतिवेदनों के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु, सभी प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश निर्गत किये थे (जून 1987)। अप्राप्त उत्तरों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति तालिका 1.3 में दी गयी है।

तालिका 1.3: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 जून 2022 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर		पीए/सीए के प्रस्तारों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई ³	
		पीए	सीए	पीए	सीए
अ. आर्थिक क्षेत्र (नॉन-पीएसयू)					
2012-13	01.07.2014	2	6	2	0
2013-14	17.08.2015	2	5	1	2
2014-15	08.03.2016	4	4	4	4
2015-16	18.05.2017	2	4	1	4
2016-17	19.07.2019	-	4	-	1

³ ऊर्जा विभाग; अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग; वित्त विभाग; अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; आवास एवं शहरी नियोजन विभाग; लोक निर्माण विभाग; शहरी विकास विभाग; परिवहन विभाग; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग; पर्यटन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से सम्बन्धित।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर		पीए/सीए के प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई ³	
		पीए	सीए	पीए	सीए
2017-18	21.08.2020	-	10	-	9
2018-19	19.08.2021	-	9	-	8
2019-20	17.12.2021	1 ⁴	0	1	0
योग		11	42	9	28
ब. पीएसयू					
2011-12	16.09.2013	2	14	1	1
2012-13	20.06.2014	1	19	0	1
2013-14	17.08.2015	2	15	1	4
2014-15	08.03.2016	6	12	2	3
2015-16	18.05.2017	6	11	3	0
2016-17	07.02.2019	3	7	2	4
2017-18	21.08.2020	1	12	0	5
2018-19	19.08.2020	-	06	0	1
	17.12.2021	1 ⁵	0	1	0
योग		22	96	10	19
महायोग (अ+ब)		33	138	19	47

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

- लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श वर्ष 2012-13 से 2019-20 के दौरान इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागों/स्वायत्त निकायों से सम्बन्धित, 11 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 42 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को प्रस्तुत किया गया। इनमें से, लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 13 प्रस्तरों (पीए/सीए) को विचार-विमर्श के लिए चयनित किया। 30 जून 2022 को पीएसी द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति तालिका 1.4 में दी गयी है।

तालिका 1.4: पीएसी द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2019-20 के लिए आर्थिक क्षेत्र की पीए/सीए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	53 (11 पीए ⁶ + 42 सीए)
पीएसी द्वारा विचार-विमर्श हेतु लिए गए	13 (5 पीए + 8 सीए)
पीएसी द्वारा की गयी अनुशंसा	शून्य
प्राप्त कृत-कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	-

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

- सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (कोपू) का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श

वर्ष 1982-83 से 2019-20 के दौरान, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सम्बन्धित, 160 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 1,010 अनुपालन लेखापरीक्षा

⁴ उत्तर प्रदेश में 'नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का आवंटन' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

⁵ उत्तर प्रदेश में 'राज्य ऊर्जा उपक्रमों द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी बिलिंग' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

⁶ उत्तर प्रदेश में 'नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का आवंटन' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए।

प्रस्तरों को प्रस्तुत किया गया। इनमें से, कोपू ने 154 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 1,021 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को विचार-विमर्श के लिए चयनित किया। 30 जून 2022 को कोपू द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति तालिका 1.5 में दी गयी है।

तालिका 1.5: कोपू द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

स्थिति	वर्ष 1982-83 से 2019-20 के लिए पीएसयू की पीए/सीए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	1,170 (160 पीए ⁷ + 1,010 सीए)
कोपू द्वारा विचार-विमर्श हेतु लिए गए	1,175 (154 पीए + 1,021 सीए) ⁸
कोपू द्वारा की गयी अनुशंसा	270 (29 पीए + 241 सीए)
प्राप्त कृत-कार्यवाही टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	-

स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा की स्थिति

1.5 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए सौंपे गए राज्य सरकार के संस्थाओं के शासी अधिनियमों/शासनादेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, इन संस्थाओं के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किये जाने हैं तथा वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं के साथ राज्य विधान मण्डल में सरकार द्वारा रखे जाने हैं।

• संस्थाओं के बकाया लेखों के अन्तिमीकरण एवं उनकी प्रस्तुति

31 मार्च 2021 तक, उत्तर प्रदेश के 11 संस्थाओं के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी थी। 30 जून 2022 तक, किसी भी संस्था ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया था और 2020-21 तक 85 लेखें बकाये थे। वर्ष जिनके लिए वार्षिक लेखे बकाया हैं का विवरण तालिका 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.6: विभिन्न संस्थाओं के लेखों के बकाये का विवरण

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
1	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2020-21	03
2	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2020-21	16
3	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2020-21	16
4	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2020-21	16
5	सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2020-21	16
6	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2020-21	03
7	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2020-21	01
8	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	04
9	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	2019-20 एवं 2020-21	02
10	क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	2014-15 से 2020-21	07
11	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	2020-21	01
योग			85

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

⁷ (1) 'उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों का विक्रय' (2) उत्तर प्रदेश में 'राज्य ऊर्जा उपक्रमों द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी बिलिंग प्रणाली' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित है।

⁸ कोपू द्वारा वर्ष 1976-77 से 2019-20 तक चर्चा किये गए पीए/सीए सम्मिलित हैं।

राज्य विधान मण्डल में संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

1.6 तीन संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखे जिनको राज्य विधान मण्डल में 30 जून 2022 तक रखा जाना बाकी है, का विवरण तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जाने हेतु बकाया वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष जहाँ तक वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जा चुके हैं	विधान मण्डल में प्रस्तुत न किये गए वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर की स्थिति	
			वार्षिक प्रतिवेदन/लेखों के साथ एसएआर का वर्ष	सरकार को एसएआर निर्गत करने की तिथि
1	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)	स्थापना के बाद से विधान मण्डल में कोई एसएआर नहीं रखा गया (2003-04)	2003-04	19 अक्टूबर 2006
			2004-05	5 अक्टूबर 2007
			2005-06	5 अक्टूबर 2007
			2006-07	3 अक्टूबर 2008
			2007-08	17 अगस्त 2009
			2008-09	15 अगस्त 2010
			2009-10	26 मई 2011
			2010-11	08 जून 2012
			2011-12	24 सितम्बर 2014
			2012-13	20 फरवरी 2015
			2013-14	22 जून 2015
			2014-15	28 दिसम्बर 2015
			2015-16	18 मई 2017
			2016-17	8 मार्च 2019
2017-18	15 मई 2020			
2018-19	18 दिसम्बर 2020			
2	क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	शून्य	2010-11	2 मई 2019
			2011-12	1 अक्टूबर 2019
			2012-13	1 अक्टूबर 2019
			2013-14	6 अप्रैल 2022
3	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए)	शून्य	2007-08	3 जुलाई 20019
			2008-09	10 जून 2020
			2009-10	18 दिसम्बर 2020
			2010-11	10 अगस्त 2020
			2011-12	29 मार्च 2022
			2012-13	12 अप्रैल 2022
			2013-14	27 अप्रैल 2022
			2014-15	26 मई 2022
2015-16	20 जून 2022			

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

1.7 लेखापरीक्षा के दौरान तीन विभागों के सात प्रकरणों में इंगित की गयी ₹ 23.95 करोड़ की वसूली सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वीकार की गयी। जिसके विरुद्ध, छः प्रकरणों में ₹ 21.23 करोड़ की वसूली सम्पन्न की गयी जिसका विवरण तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वीकार/सम्पन्न की गयी वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूलियों का विवरण	लेखापरीक्षा में इंगित तथा विभाग/संस्था द्वारा स्वीकार की गयी वसूलियाँ		सम्पन्न की गयी वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि	प्रकरणों की संख्या	शामिल धनराशि
ऊर्जा विभाग	टैरिफ के गलत अनुप्रयोग के कारण राजस्व की हानि ⁹	4	10.16	3	6.62
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	अनुचित योजना और खराब अनुवर्ती कार्यवाही के परिणामस्वरूप ईएमसी परियोजना का परित्याग और यूपीएलसी की प्रतिभूति जमा की जम्बी ₹ 5.75 करोड़	1	5.75	1	5.75
लोक निर्माण विभाग	अनुबंध के निष्पादन से पहले मशीनरी की खरीद के लिए ठेकेदार को अग्रिम भुगतान	1	6.98	1	8.06
	ठेकेदार को वस्तु एवं सेवा कर का अतिरिक्त भुगतान	1	1.06	1	0.80
योग		7	23.95	6	21.23

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

निष्कर्ष

1.8 लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत नहीं करना, अधिकांश राज्य संस्थाओं के वार्षिक लेखे तैयार करने में अधिक बकाया और राज्य विधान मण्डल में एसएआर के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखे नहीं प्रस्तुत करना सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए यह चिंता का कारण है।

⁹ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के दो प्रकरणों, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का एक प्रकरण और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एक प्रकरण से सम्बन्धित।

